

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3937

बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

कारोबार करने में सुगमता की भारतीय रैंकिंग

3937. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कारोबार करने में सुगमता की रैंकिंग में सुधार हुआ है और यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप भारत को कुछ लाभ होगा;
- (ख) क्या सरकार की देश में जिला स्तरीय कारोबार करने में सुगमता की रैंकिंग के प्रस्ताव की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश को किस हद तक सहायता प्रदान किए जाने का विचार है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

- (क): जी हां। विश्व बैंक द्वारा 31 अक्टूबर, 2018 को जारी नवीनतम ड्रिंग बिजनेस रिपोर्ट, 2019 में भारत का 190 देशों में 77 वां रैंक है जो पिछले रैंक के मुकाबले 23 स्थान ऊपर है। यद्यपि कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता फिर भी अनुकूल व्यवसाय परिवेश के परिणामस्वरूप देश में अधिक निवेश आया है तथा मौजूदा निवेश की दक्षता में सुधार आया है।
- (ख): व्यवसाय सुधार कार्यक्रम को मूल स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा एक जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्रवाई योजना तैयार की गई है तथा इसे सभी राज्यों और संघीय राज्यों के साथ सांझा किया गया है। जिला सुधार योजना के अनुसार राज्यों/संघीय राज्यों को वेब पोर्टल बनाने ऑन लाइन सिस्टम, सेवा सुपुर्दगी हेतु अनिवार्य समय सीमा तथा आवेदक एवं विभाग/एजेंसी के बीच संपर्क बिंदुओं को समाप्त करना अपेक्षित है। जिले को ऑन लाइन सिस्टम अपनाना होता तथा राज्य द्वारा नियत अनिवार्य समय सीमा का अनुपालन करना होता है। एक सुझावित प्रश्नावली भी बनाई गई है तथा राज्य में फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्हें राज्यों को भेजा गया है।
- (ग): डीपीआईआईटी, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों तथा संघीय राज्यों की विभिन्न स्तर के सतत प्रयासों के माध्यम से व्यवसाय सुधार कार्यान्वयन में सहायता करता है। कार्रवाई योजना पर विचार विमर्श करने तथा राज्यों/संघीय राज्यों की विशिष्ट प्रश्नावली का समाधान करने के लिए राज्यों/संघीय राज्यों के साथ अनेक वीडियो सम्मेलन तथा क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। मुम्बई, महाराष्ट्र में दिनांक 8 जनवरी, 2019 को एक पश्चिमी एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों ने भाग लिया था।
